was the Minister dealing with this Ministry. We referred to certain charges and discussed in Parliament then. Are all these washed away or expunged ? We have been told that charges have been framed against the PTI management. Now the Minister says she has not received.

SHRIMATI NANDINI SATPATHY : I have not said I have not received. I said I do not have the information with me but if there are any charges definitely we will look into them and see what Government can do in the matter.

SHRI A.N. VIDYALANKAR : Is it not—fact that these are not independent because these agencies are controlled by the newspaper editors who are under the big industrialists ?

SHRIMATI NANDINI SATPATHY : Yes, Sir. We know that some of the big newspapers are share-holders and directors in these news agencies.

SHRI ANANTRAO PATIL : May I know from the Minister whether it is a fact that the Members of the Board of Directors consisting of mainly the tycoons of the news-papers are only looking after the welfare of their papers and whether it is also a fact that the subscription of the PTI is prohibitive for small and medium news-papers ?

MR. SPEAKER : You need not give information ; you may just ask a question.

SHRIMATI NANDINI SATPATHY : I could not follow the second part.

SHRI ANANTRAO PATIL : I asked whether the subscription of PTI is prohibitive for small and medium news-papers.

SHRIMATI NANDINI SATPATHY : Just now I do not have information as to what is the subscription for small and medium news-papers.

SHRI R. K. SINHA : PTI and UNI have monopoly in the matters of news coverage and they don't give correct news. This vitiates the view of the people of the country. I would like to know whether we could take immediate steps to convert them into independent Corporation controlled by eminent journalists etc. so that the people are fed with objective, reliable and correct news.

SHRIMATI NANDINI SATPATHY : This question of converting them into statutory corporation is under the consideration of the Government. That is what I said in the beginning. While taking this into consideration, we will certainly keep in mind the suggestion made by the hon. Member.

विश्व की मंडी में बड़े इंजीनियरिंग ठेके प्राप्त करने में भारतीय फर्मों की असफलता

*371. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंजीनियरिंग निर्यात विकास परिषद् ने एक रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि विश्व प्रतिस्पर्धा के कारण अधिकांश मामलों में भारतीय वाणिज्यिक फर्में बड़े इंजीनियरिंग ठेके प्राप्त करने की स्थिति में नहीं हैं ;

(ख) क्या उक्त परिषद् ने यह भी उल्लेख किया है कि विश्व की मंडियों में इंजीनियरिंग ठेके प्राप्त करने के लिये प्रतिस्पर्धा करने हेतु यह आवश्यक है कि इंजीनियरिंग संगठनों, सलाहकार विशेषज्ञों और राज्य व्यापार निगम में समन्वय हो ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एस. एस. सिंघ) : (क) से (ग) . एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) जी नहीं। भारतीय निर्यात सदन, विश्व प्रतिस्पर्धा के बाद भी, विश्वव्यापी निविदाओं के लिए बोली देकर भारी मूल्य की बहुत सी संविदाएं और आद्योपान्त (टर्न की) परियोजनाएं प्राप्त करने में सफल रहें हैं।

(ख) और (ग) . भारी मूल्य की संविदाओं और परियोजनाओं में भाग लेने के लिए पहली शर्त यह है कि निर्यात सदन तथा अनेक संगठनों, जैसे कि निर्माताओं पूर्तिकर्त्ताओं इंजीनियरी-परामर्शकों और सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों की वित्तीय संस्थाओं के बीच समन्वय हो और ऐसा होने के कारण भारी मूल्य की संविदाओं के प्रस्तावों पर शीघ्रतापूर्वक विचार किया जाता है और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या मंत्री महोदय ने इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट डेवेलपमेंट कौंसिल की रिपोर्ट पढ़ी है, जिस में यह कहा गया है कि हमें फिलिपाइन्ज और सूडान में चीनी की मिलें खोलने के बारे में अवसर मिला था, लेकिन हम ने उसे खो दिया? इसी तरह के और भी तथ्य उस रिपोर्ट में दिये गये हैं। क्या मंत्री महोदय ने वह रिपोर्ट नहीं देखी है? अगर देखी है, तो विवरण के (क) में दिये गये "जी नहीं" का क्या मतलब है?

श्री एल. एन. मिश्र : इस "जी नहीं" का ताल्लुक उस रिपोर्ट से नहीं है माननीय सदस्य ने पूछा है कि क्या विश्व प्रतिस्पर्धा के कारण भारतीय वाणिज्यिक फ़र्में अधिकांश मामलों में बड़े इंजीनियरिंग ठेके प्राप्त करने की स्थिति में नहीं हैं। उस के जवाब में "नहीं" कहा गया है। हमारे इंजीनियरिंग गुड्ज का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है और गवर्नमेंट इस सम्बन्ध में सभी सुविधायें देती रही है। अगर इस में कुछ कठिनाइयां हैं, तो हम देखेंगे कि उस की ख़ास वजह क्या है। माननीय सदस्य को यह जान कर खुशी होगी कि पहले हम 41 करोड़ के इंजीनियरिंग गुड्ज का एक्सपोर्ट करते थे, जो कि अब बढ़ कर 115 करोड़ का हो गया है। माननीय सदस्य को यह जान कर भी खुशी होगी कि हमारे इंजीनियरिंग गुड्ज जापान, जर्मनी, विलायत और अमरीका आदि देशों में भी जाते हैं। इस के अलावा हम कुछ जायंट वेन्चर्ज भी कर रहे हैं, जिस में हम ख़ास तौर से अफ्रीकी देशों और अन्य देशों में उन के साथ मिल कर बड़े बड़े कारख़ाने लगाना चाहते हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट डेवेलपमेंट कौंसिल ने कहा है कि जो ग्लोबल टेंडर होते हैं, जो विश्व के पैमाने पर टेंडर मंगाये जाते हैं, उन में छोटे छोटे उद्योग वाले प्रतियोगिता नहीं कर सकते, इस लिए इस के लिए एक कानसर्टम होना चाहिए, जिस में छोटे उद्योगों का भी प्रतिनिधित्व हो और जो विश्व की प्रतियोगिता में ठहर सके। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इस सुझाव पर विचार किया है।

श्री एल. एन. मिश्र : यह सही है कि काम्पीटीशन, प्रतियोगिता, काफी है, ख़ास तौर से टेकनीकल नी-हाऊ और डिजाइन्ज में। और पूंजी का भी अभाव है। हम इन तीनों समस्याओं को देख रहे हैं। इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रोमोशन कौंसिल के साथ बातचीत चल रही है कि आर्थिक - फ़िनांशल और टेकनीकल एसिस्टेंस आदि क्या सुविधायें दी जायें, ताकि हम बाहर के देशों में कम्पीट कर सकें और वहां हमारा माल बेचा जा सके।